

—: प्रश्नोत्तरी :-

प्रश्न—जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत विभाग द्वारा मनोरंजन से सम्बन्धित कौन-कौन सी सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं ?

उत्तर—जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत विभाग द्वारा मनोरंजन से सम्बन्धित निम्नलिखित चार सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं—

1. एकल सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, सचल सिनेमा/विशेष चलचित्र प्रदर्शन, वीडियो सिनेमा, सचल वीडियो सिनेमा, स्थानीय चैनल और वीडियो लाइब्रेरी हेतु नवीन लाइसेंस।
2. एकल सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, सचल सिनेमा/विशेष चलचित्र प्रदर्शन, वीडियो सिनेमा, सचल वीडियो सिनेमा, स्थानीय चैनल और वीडियो लाइब्रेरी के लाइसेंस का नवीनीकरण।
3. चलचित्र/डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के लिए आपरेटर परमिट।
4. विभिन्न मनोरंजन के लिये अनुमति (लाइसेंसड मनोरंजन, केबिल और डी.टी.एच. को छोड़कर यथा मनोरंजन पार्क/वॉटर पार्क, कैबरे या फ्लोर शो, झूला, वीडियो गेम्स, कौशल के खेल, मिमिकरी, कार्निवाल, पपेट शो, अशास्त्रीय संगीत, घुड़दौड़, पूल गेम, बॉलिंग येले, बिलियर्ड्स, स्नूकर तथा उक्त सूची के अतिरिक्त अन्य मनोरंजन)

वर्तमान में विभाग द्वारा उपरोक्त सेवाओं को आनलाईन भी कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति उक्त सेवाओं को प्राप्त करने हेतु विभागीय एप्लिकेशन <http://up-gst.com/entertainmenttax/> पर आनलाईन आवेदन कर सकता है।

प्रश्न—किन-किन मनोरंजन से सम्बन्धित सेवाओं के संचालन के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है ?

उत्तर—एकल सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, सचल सिनेमा/विशेष चलचित्र प्रदर्शन, वीडियो सिनेमा, सचल वीडियो सिनेमा, स्थानीय चैनल और वीडियो लाइब्रेरी के संचालन हेतु लाइसेंस की आवश्यकता होती है।

प्रश्न—किन-किन मनोरंजन से सम्बन्धित सेवाओं के संचालन के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है ?

उत्तर—लाइसेंसड मनोरंजन, केबिल और डी.टी.एच. को छोड़कर अन्य मनोरंजक कार्यक्रम जैसे मनोरंजन पार्क/वॉटर पार्क, कैबरे या फ्लोर शो, झूला, वीडियो गेम्स, कौशल के खेल, मिमिकरी, कार्निवाल, पपेट शो, अशास्त्रीय संगीत, घुड़दौड़, पूल गेम, बॉलिंग येले, बिलियर्ड्स, स्नूकर आदि के संचालन से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट से नियमानुसार अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

प्रश्न—यदि कोई व्यक्ति प्रदेश में एकल सिनेमा अथवा मल्टीप्लेक्स बनाना चाहता है। तो इसके लिए कहाँ आवेदन करना होगा तथा क्या-क्या जरूरी कागजात और औपचारिकताओं की आवश्यकता होती है ?

उत्तर—एकल सिनेमा अथवा मल्टीप्लेक्स निर्माण के इच्छुक व्यक्ति द्वारा सम्बन्धित सक्षम प्राधिकरण (यथा विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, विनियमित क्षेत्र अथवा अन्य कोई प्राधिकरण) को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें योजना और विनिर्दिष्टियों सहित वह स्थल विनिर्दिष्ट होगा जहाँ पर प्रस्तावित भवन निर्मित किया जाना है।

उल्लिखित योजना में भवनों की ऊंचाइयां और खण्ड, प्रस्तावित विद्युत प्रतिष्ठापन, संवातन, स्वच्छता अथवा वाहन पार्किंग की व्यवस्था और 200 मीटर के अर्द्ध व्यास के भीतर पार्श्वस्थ परिसर से सम्बन्धित परिसर की स्थिति और सार्वजनिक मार्ग जिससे भवन सटा हो, सम्मिलित होंगे।

यदि सक्षम प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि स्थल योजनाएं और विनिर्देश पूर्णतः नियमावली (सिनेमा भवन निर्माण के सुसंगत उपबन्ध), उत्तर प्रदेश चित्रचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 और उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ रूल्स, 1951 तथा लागू भवन उपविधियों के अनुरूप है तो वह आवेदन को स्थल योजना और तत्सम्बन्धी निविदेशों के अनुसार उसका अनुमोदन संज्ञापित करते हुए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक से 60 दिन के भीतर प्रमाण-पत्र प्रदान कर सकता है।

प्रश्न—नवनिर्मित सिनेमा/मल्टीप्लेक्स का लाइसेंस कौन स्वीकृत करता है तथा लाइसेंस हेतु किन-किन औपचारिकताओं को पूर्ण करना पड़ता है तथा यह आवेदन के कितने दिन के अन्दर स्वीकृत होगा ?

उत्तर—नवनिर्मित सिनेमा/मल्टीप्लेक्स के लाइसेंस स्वीकृत हेतु लाइसेंस प्राधिकारी सम्बन्धित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट होंगे। आवेदक को लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ नियमावली, 1951 की परिशिष्ट-तीन में उल्लिखित प्रपत्र में, परिसर और चलचित्र मशीन/डिजिटल प्रोजेक्शन मशीन के स्वामित्व की पूर्ण विशिष्टियों सहित निम्नलिखित अभिलेखों के साथ प्रस्तुत किया जायेगा—

(क) सुसंगत उपबन्धों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित मौलिक स्थल एवं परिसर योजना सहित परिसर तथा चलचित्र प्रोजेक्टर/डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के स्वामित्व और 200 मीटर अर्द्धव्यास के भीतर पार्श्वस्थ परिसर से सम्बन्धित परिसर और सार्वजनिक मार्ग जिससे भवन सटा हो, की अवस्थिति का प्रमाण पत्र।

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुसंगत उपबन्धों के अधीन अनुमोदित भवन योजना सहित मूल सन्निर्माण आदेश, जिसमें भवन की उचाईयां तथा खण्ड, प्रस्तावित विद्युत प्रतिष्ठापन, संवातन, स्वच्छता तथा वाहन पार्किंग की व्यवस्था सम्मिलित हैं।

(ग) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुसंगत उपबन्धों के अधीन अनुमोदित प्रत्येक वर्ग के लिए अलग-अलग बैठने की व्यवस्था सम्बन्धी योजना।

(घ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी संरचनात्मक सुरक्षा तथा स्थायित्व संबंधी अनापत्ति प्रमाणपत्र सहित पूर्णता प्रमाण पत्र/ अधिभोग प्रमाण-पत्र।

(ङ.) सम्बन्धित क्षेत्र के विद्युत सुरक्षा विभाग के उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का यह प्रमाण पत्र कि विद्युत अधिष्ठापन अपेक्षित मानकों और विद्यमान नियमों और उपविधियों के अनुरूप हैं।

(च) उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ रूल्स, 1951 के नियम-13 और भवन एवं विकास उपविधियों की अपेक्षाओं के अनुरूप स्वच्छता व्यवस्था का विवरण;

(छ) सम्बन्धित क्षेत्र के मुख्य अग्निशमन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी (अग्निशमन) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, जिसकी अधिकारिता हो, का यह प्रमाण पत्र कि उपलब्ध कराये गये अग्निशमन साधनों की व्यवस्थाएं और अग्नि के विरुद्ध अपनायी गयी सावधानियाँ विद्यमान नियमों और उपविधियों के अनुरूप हैं।

(ज) आवश्यक संदाय लाइसेंस शुल्क

सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर लाइसेंस प्राधिकारी आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के दिनांक के पश्चात 30 दिन के भीतर लाइसेंस स्वीकृत करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाता है।

प्रश्न—विभिन्न आमोदों के लाइसेंस/लाइसेंस नवीनीकरण हेतु क्या शुल्क निर्धारित हैं ?  
उत्तर—विभिन्न आमोदों के लाइसेंस/लाइसेंस नवीनीकरण हेतु शुल्क निम्नलिखित हैं—

- चलचित्र/डिजिटल प्रोजेक्शन के माध्यम से प्रदर्शन के लिए लाइसेंस फीस—  
(एक) किसी स्थायी सिनेमा के लिए निम्नलिखित जनसंख्या वाले किसी स्थानीय क्षेत्र में स्थायी लाइसेंस प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए  
(क) एक लाख तक के लिए—प्रति माह या उसके आंशिक भाग के लिए 3000.00 (तीन हजार) रुपये,  
(ख) एक लाख से अधिक के लिए—प्रतिमाह या उसके आंशिक भाग के लिए 5000.00 (पाँच हजार) रुपये,
- सचल सिनेमा के लिए कोई अस्थायी लाइसेंस प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए निम्नलिखित अवधि हेतु उसके सम्मुख अंकित लाइसेंस फीस होगी—  
(क) अनधिक एक माह— 500.00 रुपये,  
(ख) एक माह से अधिक किन्तु तीन माह से अनधिक— 1500.00 रुपये  
(ग) तीन माह से अधिक किन्तु अनधिक छः माह— 3000.00 रुपये
- वीडियो चलचित्र, होटल, सार्वजनिक सेवायान अथवा चल वीडियो चलचित्र के लाइसेंस दिये जाने या उसके नवीकरण के लिए शुल्क निम्नलिखित होगा—

क्र० सं०	मनोरंजन	शुल्क
(एक)	वीडियो चलचित्र जिसमें किसी केबिल टेलीविजन नेटवर्क के मामले में वीडियो द्वारा प्रदर्शन सम्मिलित है।	प्रति वीडियो कैसेट प्लेयर प्रति वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए 5000 रुपये।
(दो)	होटल	प्रति वीडियो कैसेट प्लेयर प्रति वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए 2500 रुपये।
(तीन)	सार्वजनिक सेवा यान	प्रति वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए 2500 रुपये।
(चार)	किसी स्थानीय क्षेत्र में चल वीडियो चलचित्र।	
	(क) उस स्थानीय क्षेत्र में वीडियो चलचित्र प्रारंभ होने के दिनांक से प्रारंभिक एक वर्ष की अवधि तक लाइसेंस प्रदान किये जाने या उसके नवीकरण के लिए।	प्रतिमास या उसके आंशिक भाग के लिये 200 रुपये।
	(ख) उस स्थानीय क्षेत्र में वीडियो चलचित्र प्रारंभ होने के एक वर्ष की समाप्ति की निरन्तरता में लाइसेंस प्रदान करने या उसके नवीकरण के लिए।	प्रतिमाह या उसके आंशिक भाग के लिये 200 रुपये।

- वीडियो लाइब्रेरी हेतु एक वित्तीय वर्ष अथवा उसके भाग के लिए स्थानीय क्षेत्र निम्नलिखित लाइसेंस शुल्क होगा—

स्तम्भ-1 (स्थानीय क्षेत्र)	स्तम्भ-2 (वीडियो लाइब्रेरी हेतु लाइसेंस शुल्क )
(क) नगर निगम, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा	पाँच हजार रुपये
(ख) नगर पालिका परिषद	तीन हजार रुपये
(ग) टाऊन एरिया / अन्य स्थान	एक हजार पाँच सौ रुपये

प्रश्न—सिनेमा निर्माण हेतु आवेदन करने पर विभाग द्वारा कितने समय के अन्तराल में सिनेमा निर्माण करने की अनुमति दी जाती है।

उत्तर—सिनेमा का साइट प्लान नियमानुसार पाये जाने पर एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने पर सिनेमा निर्माण हेतु आवेदन करने के 60 दिन के अन्दर सिनेमा निर्माण हेतु सम्बन्धित सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमति दी जाती है।

प्रश्न—सिनेमा भवन तैयार होने के बाद लाइसेंस लेने के लिए कोई समय सीमा तय है?

उत्तर—सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पूर्ण संतुष्टि के बाद कि सिनेमा स्वामी द्वारा नियमों के अन्तर्गत सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं तो लाइसेंस उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमवाली, 1951 के नियम 9 के अंतर्गत जारी किया जाता है, जो एक बार में अधिकतम पाँच वर्षों के लिये जारी किया जा सकता है। उ0प्र0 जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत सिनेमा लाइसेंस हेतु सभी दृष्टियों से पूर्ण आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के 30 दिन के अन्दर लाइसेंस प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) द्वारा सिनेमा लाइसेंस प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाता है।